शुगर मिलों के राहत पैकेज पर पवार से मिले थॉमस

शुगर इंपोर्ट पर पाबंदी लगाए जाने और कच्ची चीनी के लिए इंसेंटिव जैसे उपायों पर बातचीत

[पीटीआई | नई दिल्ली]

फूड मिनिस्टर के वी थॉमस ने मंगलवार को एग्रीकल्चर मिनिस्टर शरद पवार से शुगर इंडस्ट्री के लिए राहत उपायों पर चर्चा की। शुगर इंडस्ट्री कैश के संकट से जूझ रही है। बैठक में शुगर इंपोर्ट पर पाबंदी लगाए जाने और कच्ची चीनी के लिए इंसेंटिव जैसे उपायों पर बातचीत हुई।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शरद पवार की अगुवाई में शुगर इंडस्ट्री की समस्याओं से निपटने के लिए मंत्रियों के एक समूह की अनौपचारिक कम्मेटी बनाई है। केंद्र सरकार पहले ही पैनल की एक अहम सिफारिश लागू कर चुकी है।

इसके तहत शुगर मिलों को गन्ना किसानों के बकाए के भुगतान के लिए बिना ब्याज के 6,600 करोड़ रुपये के लोन देने का ऐलान किया गया है।

फूड मिनिस्टर ने बताया, 'एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ मुलाकात में शुगर मिलों के लिए अतिरिक्त इंसेंटिव पर चर्चा हुई। हमने पैनल की बाकी सिफारिशों खास तौर पर कच्ची चीनी के प्रॉडक्शन को इंसेंटिव देने पर भी चर्चा की।' चीनी की घरेलू कीमत कम रहने से इंडस्ट्री का एक तबका कच्ची चीनी के इंपोर्ट पर पाबंदी लगाने के पक्ष में है। फूड मिनिस्टर थॉमस ने कहा, 'बैठक में इस मसले पर भी चर्चा हुई। री-एक्सपोर्ट के लिए कच्ची चीनी का इंपोर्ट किया जा रहा है।' उन्होंने कहा कि इन मसलों पर मंत्री समूह की अगली बैठक में भी विचार किया जाएगा। यह बैठक जल्द होगी।

इस पैनल में थॉमस के अलावा फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदंबरम, पेट्रोलियम मिनिस्टर वीरप्पा मोइली और सिविल एविएशन मिनिस्टर अजीत सिंह शामिल हैं। पैनल की बाकी सिफारिशों में आरबीआई नॉर्म्स के तहत लोन रीस्ट्रक्चरिंग, 40 लाख तक कच्ची चीनी के प्रॉडक्शन के लिए इंसेंटिव और बफर स्टॉक बनाए जाने के अलावा पेट्रोल में एथनॉल की मात्रा बढ़ाकर 10 फीसदी किए जाने की बात है।

प्रॉडक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी और कीमतों में कमी के कारण शुगर इंडस्ट्री को फाइनेंशियल संकट का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ साल में शुगर का प्रॉडक्शन ज्यादा हुआ है, जिससे इसकी कीमत बढ़ नहीं रही है।

शुगर इंडस्ट्री के पास गन्ना किसानों का पिछले साल का 3,400 करोड़ रुपये बकाया है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु अहम शुगर प्रॉडक्शन करने वाले राज्य हैं। मार्केटिंग ईयर 2013-14 (अक्टूबर-सितंबर) में शुगर प्रॉडक्शन 2.14 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो अनुमानित घरेलू खपत 2.35 करोड़ टन से ज्यादा है।

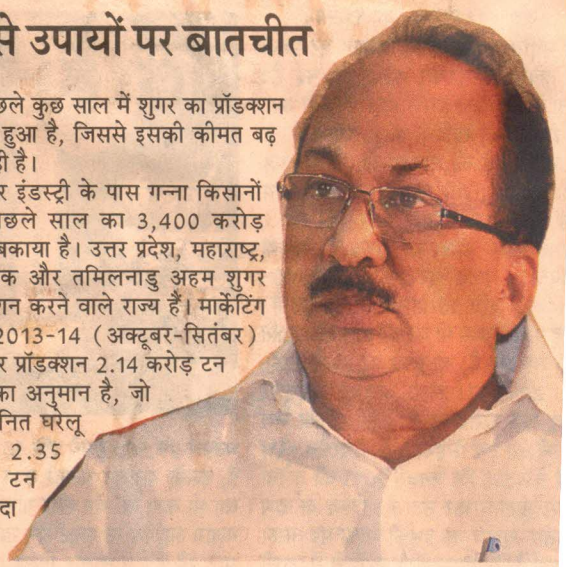

Economic Times

15/1/14